अपनी बात

तिब्बत की वास्तविक स्वायत्तता की मांग प्रासंगिक

निर्वासित सरकार के प्रधानमन्त्री (सिक्योंग) डॉ. लोबसांग सांगे ने गत 5 जून 2014 को ''मध्यम मार्ग'' संस्था के एक नए वेबसाइट की शुरूआत की। मध्यम मार्ग की मांग है कि तिब्बत को चीन सरकार वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करे। तिब्बत समर्थक अधिकांश संगठन चाहते हैं कि तिब्बत को पूर्ण आजादी मिले किन्तु काफी सोच–विचार के बाद तिब्बती धर्मगुरु परमपावन दलाई लामा तथा तिब्बत की निर्वासित सरकार ने चीन से केवल वास्तविक स्वायत्तता की मांग की है। इसी का नाम है मध्यम मार्ग। चीन के संविधान और कानूनों में वास्तविक स्वायत्तता संबंधी प्रावधान मौजूद हैं। इस प्रकार इस मांग से साफ पता चलता है कि तिब्बत सरकार चीन के संविधान एवं कानून का पूरा सम्मान करती है। प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले तथा वित्तीय मामले चीन सरकार अपने पास रखे। शेष सभी विषय तिब्बत सरकार के हवाले कर दे। शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण, धर्म, कृषि, उद्योग, भाषा तथा प्राकृतिक संसाधन संबंधी कानून तिब्बत सरकार बनाए। इससे चीन की संप्रभुता का सम्मान होने के साथ ही तिब्बतियों को स्वशासन के अधिकार मिल जायेंगे।

वेबसाइट के प्रारम्भ के पीछे परमपावन दलाई लामा जी की प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद है। दलाई लामा लोकतंत्र के प्रबल समर्थक हैं। पहले वे धार्मिक के साथ–साथ राजनीतिक कार्य भी किया करते थे। वे तिब्बत के धार्मिक प्रधान के साथ ही राजनीतिक प्रधान भी थे। धीरे–धीरे उन्होंने राजनीतिक जिम्मेदारियों से स्वयं को दूर करना शुरू कर दिया। वर्ष 2001 से तिब्बती जनता द्वारा कालोन ट्रिपा (प्रधानमंत्री) का चुनाव किया जाने लगा है। वर्तमान प्रधानमंत्री (सिक्योंग) डॉ. लोबसांग सांगे को दलाई लामा अपने संपूर्ण राजनीतिक दायित्व सौंप चुके हैं। अब वे अपने आपको केवल धार्मिक दायित्व तक ही सीमित कर चुके हैं। उनका स्पष्ट मत है कि चीन सरकार की दमनात्मक नीति से तिब्बत की पहचान भी संकट में है। इस पहचान को बचाने के लिए वास्तविक स्वायत्तता अर्थात मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम उपाय है। चीन के अधीन रहते हुए भी तिब्बत के मूल्यों, प्राकृतिक संपदा तथा तिब्बती पहचान की सुरक्षा कर लेना तभी संभव होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यम मार्ग नीति को बढ़ता सहयोग–समर्थन सराहनीय है।

लेकिन चीन सरकार अपना हठ छोड़ने को तैयार नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चीनी प्रधानमंत्री के साथ वार्ता से पहले अभी जून में ही ब्रिटेन के उपप्रधानमंत्री ने तिब्बत में जारी मानवाधिकारों के हनन की विशेष रूप से चर्चा की थी। इसी प्रकार चेक गणराज्य के सिनेटर पीटर ब्राट्स्की ने तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चेक सांसदों की वार्ता के समय तिब्बत के गंभीर संकट की विस्तार से चर्चा की। उस वार्ता में चीन की उपनिवेशवादी नीति की खुलकर आलोचना की गई। ज्ञातव्य है कि चीन सरकार की तिब्बत में जारी क्रूरता के कारण दर्जनों शांतिप्रिय अहिंसक तिब्बती आंदोलनकारी ''आत्मदाह'' जैसे कदम उठा चुके हैं। यह सिलसिला अब भी जारी है।

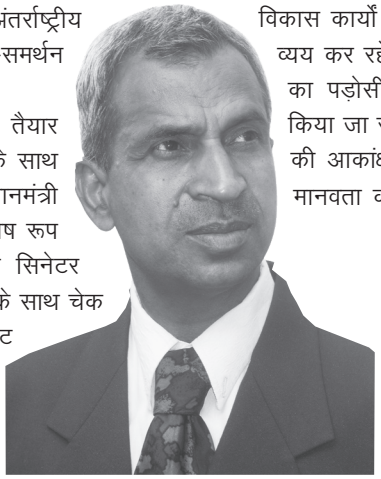

तिब्बत में जारी चीनी दमन से भारत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भारत सरकार को इस मामले में कठोर नीति अपनानी चाहिए। तिब्बत को हड़पने के बाद चीन सरकार भारत की एकता–अखंडता तथा संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। वह हर तरह से भारत को कमजोर कर रही है। वह भारत को अपमानित करने के हथकंडे अपनाती रहती है। जब तक तिब्बत फिर से आजाद नहीं हो जाता तब तक ''हिन्दी–चीनी भाई–भाई'' का नारा केवल बकवास है। तिब्बत चूंकि भारत का प्राचीन काल से पड़ोसी है, इसलिये तिब्बतियों को भारत से अधिक सहयोग की उम्मीद है। विश्व के अन्य देष भी तिब्बत मामले में भारत की चीन के समक्ष नीति पर नजरें टिकाए रहते हैं। इसी जून 2014 में पेरिस में तिब्बत महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। वहां भी भारत द्वारा तिब्बतियों को किए जा रहे सहयोग की भरपूर सराहना की गई तथा आशा की गई कि भारत सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए चीन सरकार के साथ गंभीरतापूर्वक प्रयास करेगी।

दलाई लामा बार–बार कह रहे हैं कि चीन की जनता से उनका कोई विरोध नहीं है। हाल के अपने लद्दाख प्रवास में भी उन्होंने सबके प्रति करुणा–मैत्री के भाव प्रकट किए। उनकी शांतिपूर्ण अहिंसक लड़ाई चीन सरकार की साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ है। चीन सरकार की साम्राज्यवादी नीति का षिकार भारत भी है। इस प्रकार तिब्बत मामले के समाधान में ही भारत का राष्ट्रीय हित निहित है। भारतीय चाहते हैं कि तिब्बत फिर से स्वतंत्र देश बने, लेकिन भारत सरकार को चाहिये कि वह फिलहाल तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता दिलाने की दिशा में सभी जरूरी प्रयास करे।

तिब्बत समस्या का समाधान विश्वशांति, विशेषकर एशिया महादेश में शांति की अनिवार्य शर्त है। एशिया को शांति क्षेत्र बनाने में इससे मदद मिलेगी। इस समय चीन से भयभीत होकर एशिया के कई देश अपने विकास कार्यों की उपेक्षा करते हुए सीमा की सुरक्षा पर अधिकाधिक व्यय कर रहे हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है। तिब्बती भूभाग का पड़ोसी देशों के खिलाफ चीन द्वारा साजिशपूर्ण दुरूपयोग किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि चीन के साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा पर यथाशीघ्र प्रभावी रोक लगाई जाए। यह संपूर्ण मानवता के हित में होगा। ◆

प्रो0 श्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खेतड़ी (राज.)
ek-&9829806065] 8764060406
E-mail & Facebook :- shyamnathji@gmail.com

पुलिस थानों की मदद से तिब्बती मठों में थोपी जा रही 'देशभक्ति'

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 22 जून, 2014)

भिक्षुओं पर गहरी निगरानी और दखलकारी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि चीन के प्रति पूरे जोश से देशभक्ति और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी बनाए रखेंगे, चीन सरकार मठों में पुलिस थानों की स्थापना कर रही है तथा पार्टी के पदाधिकारियों को समूचे तिब्बती क्षेत्र के मठों में प्रबंधक या प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत (आइसीटी) की 20 जून की खबर के अनुसार अकेले गांसू प्रांत के एक तिब्बती काउंटी में ही 24 पुलिस थानों की स्थापना की गई है। आइसीटी ने इसके लिए 11 जून को जारी एक आधिकारिक चीनी रिपोर्ट का हवाला दिया है। कान्हलो (गन्नान) प्रशासनिक क्षेत्र के सांगछू (चीनी में शियाहे) काउंटी में हाल के वर्षों में आत्मदाह की कई घटनाएं देखी गई हैं। आइसीटी ने चीनी रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि जिस हफ्ते की यह खबर है, उसमें एक हफ्ते के भीतर पांच पुलिस थानों की स्थापना की गई है। इसे "हाल में मठों पर पुलिस निगरानी बढ़ाने के प्रयास" का हिस्सा बताया गया है।

सरकारी मीडिया ने नवंबर 2010 में यह खबर दी थी कि क्विंघई प्रांत में हर "बड़े एवं मध्यम आकार के 133 तिब्बती मठ" में एक पुलिस थाना स्थापित करने की योजना है। यह साफ किया गया था कि छोटे और सुदूर इलाकों में स्थित मठ भी इसी तरह से पुलिस नियंत्रण में रहेंगे।

मठों के परिसर के भीतर स्थायी थानों का गठन करने और इनके प्रबंधक के रूप में पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने की खबर इसके पहले भी सांगछू काउंटी के लाबरांग मठ सहित तिब्बत स्वायत्तशासी के अन्य इलाकों से आई थी, खासकर वर्ष 2008 में ज्यादातर तिब्बती इलाकों में फैली जनक्रांति के बाद जिसमें मठों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुलिस थानों के द्वारा न सिर्फ भिक्षुओं पर निगरानी रखी जाती है, बल्कि सरकार के 'देशभक्तिपूर्ण शिक्षा' और 'मठों के प्रबंधन' के लिए व्यापक एवं व्यवस्थित अभियान चलाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशासन द्वारा भेजे गए पार्टी कार्यकर्ताओं से बने कार्यदल की मदद से इन मठों की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है।

पुलिस थानों की स्थापना और प्रबंधक के रूप में पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति मठों पर नियंत्रण स्थापित करने की चीन की मौजूदा नीति का ही हिस्सा है। इसके पीछे बड़ा उद्देश्य यह है कि, पिछले कुछ वर्षों से यह लागू होने की प्रक्रिया में है, तिब्बती इलाके के करीब हर मठ को सीधे चीनी शासन के तहत लाया जाए और शहरी एवं ग्रामीण दोनों तिब्बती इलाकों में पार्टी की उपस्थिति बढ़ाई जाए।

इस तरह के सुरक्षा अभियान से अल्पकालिक रूप से स्थिरता तो लाई जा सकती है, लेकिन इससे तिब्बतियों में असंतोष बढ़ रहा है और दोनों पक्षों में तनाव बढ़ रहा है, जिससे आगे आने वाले समय के लिए ज्यादा बड़ी क्रांति का आधार बन रहा है। खबर के अनुसार धार्मिक हस्तियों ने बार–बार अनुरोध किया है कि ऐसी दखलंदाजी वाली नीतियों और नियंत्रण के अन्य तरीकों पर रोक लगाई जाए और कई वरिष्ठ धार्मिक हस्तियों ने चेतावनी भी दी है, लेकिन चीन सरकार ने इन सबको नजरअंदाज किया है।

स्वाधीन तिब्बत से जुड़े और अन्य प्रकाशनों के खिलाफ चीन शुरू करेगा अभियान

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 25 जून 2014)

चीन सरकार के प्रोपेगंडा विभाग ने 23 जून को कहा कि चीन ऐसे अवैध प्रकाशनों पर अंकुश के लिए एक नया अभियान शुरू करेगा जिनकी सामग्री में "तिब्बत की स्वाधीनता", आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद जैसी चीजें होती हैं। चीन की सरकारी शिनहुआ न्यूज ने 23 जून को यह खबर दी है। प्रेस, पब्लिकेशन, फिल्म और टेलीविजन के उप प्रमुख जियांग जियांगुओ ने 23 जून की एक बैठक में जोर दिया कि अवैध प्रकाशनों के खिलाफ अभियान से दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता और सुरक्षा कायम होगी। "अलगाववाद–विरोध, देश तोड़ने वालों का विरोध और घुसपैठ विरोध" की थीम पर आयोजित इस अभियान के तहत अवैध धार्मिक गतिविधियों और इन्हें बढ़ावा देने वाली सामग्रियों साथ ही साथ अवैध धार्मिक सूचनाओं के ऑनलाइन प्रसार पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

जियांग ने सभी स्थानीय कार्यालयों से आह्वान किया है कि वे "अलगवावाद, धार्मिक अतिवाद, आतंकवाद और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों" के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करें।

रिपोर्ट में कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ली चांगज्यांग का भी हवाला दिया गया है जिन्होंने सभी स्तर के अधिकारियों से कहा है कि वे "प्रमुख पहलुओं पर मैनेजमेंट और नियंत्रण को मजबूत करें तथा ऑनलाइन निगरानी को और गहन करें।

ब्रिटेन में चीन के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान तिब्बत समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 19 जून, 2014)

ब्रिटेन के दौरे पर गए चीनी प्रधानमंत्री ली केक्यांग का लंदन में विरोध कर रहे तिब्बती और तिब्बत समर्थक

चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग की चार दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के दौरान तिब्बत समर्थकों, फालुन गांग के समर्थकों और अन्य कई तरह के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। चीनी प्रधानमंत्री की इस यात्रा की मुख्य बात करीब 14 अरब पौंड के व्यापारिक सौदों पर होने वाला दस्तखत है। हालांकि, लंदन स्थित चीनी दूतावास ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि इन विरोध प्रदर्शनों को दबा दिया जाए और इसके लिए सैकड़ों चीनी छात्रों को जबरन जुटाया गया कि वे चीनी झंडा लहराते हुए श्री ली का स्वागत करें। श्री ली जब 17 जून को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटिश प्रधानंत्री श्री डेविड कैमरन से मिल रहे थे, उस समय भी बाहर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था।

न्यूज स्काई डॉट कॉम की 17 जून की रिपोर्ट के अनुसार एक चीनी युवती ने बताया कि चीनी दूतावास ने उनके लिए पानी के बोतलों की व्यवस्था की थी और बैंड के लिए रकम चुकाई थी जिसे इतने जोर–शोर से बजाने का आदेश था ताकि और कोई शोर न सुनाई दे। इस युवती को एक अधेड़ व्यक्ति ने चुप करा दिया। विरोध करने वाले संगठनों में फ्री तिब्बत कैम्पेनिंग ग्रुप और स्टुडेंट्स फॉर अ फ्री तिब्बत शामिल थे। फ्री तिब्बत की मीडिया मैनेजर और प्रवक्ता अलिएस्टर कुरी ने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि श्री ली का स्वागत विंडसर किले में महारानी ने किया, जबकि वह कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं। उन्होंने कहा, "ब्रिटेन ने एक बार फिर चीन को खुश करने के लिए अपनी रीढ़ झुका देने की इच्छा दिखाई है, इसलिए इस कार्रवाई का प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। वह कह रहा है कि चीन सिर्फ एक कारोबारी साझेदार नहीं है, बल्कि हम सबके लिए कुछ खास है।" उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिटेन "प्रभावी तरीके से तिब्बत के मसले को बेच रहा है" और इस मामले में उसका रवैया पाखंडपूर्ण है क्योंकि उसने फा. कलैंड आइलैंड और स्कॉटलैंड में आत्मनिर्धारण के अधिकार को मान्यता दी है।

वायस ऑफ रशिया की खबर के अनुसार ली ने अपनी यात्रा की पुष्टि करने से पहले ही महारानी से मुलाकात पर जोर दिया था, जबकि यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। दोनों के बीच यह मुलाकात 17 जून को हुई थी।

स्टुडेंट्स फॉर अ फ्री तिब्बत की पदमा डा. लमा ने बताया कि श्री ली का काफिला जब वेस्टमिंस्टर के करीब पहुंच रहा था तो वे उसे रोकने में सफल हुई थीं। न्यूज स्काई डॉट कॉम की खबर के अनुसार उन्होंने कहा, "हमारे हाथों में तिब्बती झंडे थे और हम बार–बार "तिब्बत को स्वाधीन करो", "तिब्बत से बाहर जाओ चीन" जैसे नारे लगा रहे थे, वे हमें साफ–साफ देख रहे थे, यह हमारे लिए बड़ी बात थी।"

महारानी से मुलाकात की ली की इच्छा के आगे झुक जाने को सही ठहराते हुए श्री कैमरन ने कहा कि चीन का बढ़ता प्रभुत्व "हमारे सदी की सबसे निर्धारक घटनाओं में से है" और ब्रिटेन को उम्मीद है कि इससे एक उभरते दिग्गज के साथ कारोबारी रिश्ते और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे।

नेपाल के रास्ते निर्वासित हो रहे तिब्बतियों की मदद जारी रखने का संयुक्त राष्ट्र ने दिया संकेत

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 22 जून, 2014)

20 जून के अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने सुझाव दिया है कि वह चीनी शासन वाले अपनी मातृभूमि से भागकर भारत आने वाले तिब्बतियों को सुरक्षित रास्ता मुहैया करने को सुविधाजनक बनाने के लिए काम करता रहेगा। हाल के वर्षों में ऐसे शरणार्थियों की संख्या में भारी गिरावट आई है क्योंकि सीमा के दोनों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे पलायित होकर आने वाले तिब्बतियों के चीनी सैनिकों या समय–समय नेपाल पु. लिस द्वारा किए जाने वाले गश्त से पकड़े जाने के आसार बढ़ गए हैं।

यूएनएचएसीआर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया, " अपने आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के दर्शन के लिए नेपाल के रास्ते भारत आने वाले तिब्बतियों को यूएनएचसीआर सुरक्षित पारगमन मुहैया करता है और यह सुनिश्चित करता है कि नेपाल में रहने के दौरान उनकी सुरक्षा हो तथा उनकी भौतिक जरूरतों को पूरा किया जाए।" नेपाल में ही करीब 20,000 तिब्बती रहते हैं और इनमें से ज्यादातर का कोई दस्तावेज नहीं है। चीन से लगातार दबाव की वजह से नेपाल ने न केवल उन्हें किसी दस्तावेजी पहचान देने से इनकार किया है, यहां तक कि उनके बच्चों के जन्म पंजीकरण से भी इंकार किया जाता है, बल्कि उन्हें विदेश में यात्रा करने या वहां जाकर बसने की परमिट भी नहीं दी जाती। बताया जाता है कि नेपाल सरकार ने चीन को यह वचन दिया है कि देश में रहने वाले तिब्बतियों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने की इजाजत नहीं देगा, जिससे चीन को नाराजगी हो। चीन असल में नेपाल को आर्थिक सहायता देने वाले सबसे बड़े देशों में से है।

अमेरिका जैसा ही तिब्बत में आने–जाने की छूट देने की प्रारूप विधेयक में की गई मांग

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 14 जून, 2014)

प्रतिनिधि सभा के सदस्य जोसेफ पिट्स (आर–पीए)

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 12 जून को एक द्विदलीय प्रारूप प्रस्ताव पेश किया गया (एच.आर. 4851, रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट) जिसमें यह कहा गया कि तिब्बत की जिम्मेदारी रखने वाले चीनी अधिकारियों को तब तक अमेरिका आने पर रोक लगाई जाए, जब तक चीन तिब्बत में विदेशियों को जाने की इजाजत नहीं देता। वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत (आइसीटी) ने 12 जून को यह जानकारी दी है। इस विधेयक को जिम मैकगवर्न (डी–एमए) और जोसेफ पिट्स (आर–पीए) ने पेश किया था।

चीन यह कहता रहा है कि तिब्बत का दौरा करने वाले विदेशी, खासकर पत्रकार और राजनयिक तिब्बत जाकर खुद ही वास्तविक स्थिति देखें और "दलाई गुट" की बात न सुनें। लेकिन अपने कब्जे वाले इस हिमालयी क्षेत्र में अगर उसने आवाजाही पर पूरी तरह से रोक भले न लगाई हो, लेकिन सख्त अंकुश और रोक लगा रखी है। इस विधेयक में पारस्परिकता के सिद्धांत का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार, "एक देश को पारस्परिक आधार पर दूसरे देश के नागरिकों को समान पहुंच का मौका देना चाहिए जैसे कि दूसरे देश उसके नागरिकों को देते हैं।"

कांग्रेस सदस्य मैकगवर्न ने कहा, "तिब्बत में बाहरी लोगों के जाने पर कई तरह की रोक से तिब्बती एक तरह से बाहरी दुनिया से कट गए हैं, इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय आदान–प्रदान सीमित हो गया है और वहां मानवाधिकार की स्थिति की वस्तुनिष्ठ तरीके से आकलन करने की संभावना भी सीमित हुई है।" उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य तिब्बत को एक खुला और आसानी से पहुंच वाला बनाने का है, जिसमें अमेरिकी जा सकें और तिब्बती पठार की आश्चर्यजनक दुनिया से कुछ सीख सकें–उसके प्राकृतिक सौंदर्य, उसके लोगों और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत से।"

इस विधेयक के अनुसार विदेश मंत्रालय को यह रिपोर्ट देनी होगी कि तिब्बती क्षेत्र में चीनी प्रशासन द्वारा किस तरह की पहुंच दी जा रही है और जिम्मेदार पदों पर नियुक्त चीनी अधिकारियों की एक सूची तैयार करनी होगी। यदि तिब्बती इलाकों तक पहुंच पर लगा अंकुश गैर तिब्बती इलाकों से ज्यादा है तो इससे जुड़े अधिकारियों को अमेरिका नहीं आने दिया जाएगा।

हालांकि, विधेयक में विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि, "चीनी प्रशासन ने तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में पहुंच के लिए मई 2011 से दिसंबर 2011 के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए 10 से ज्यादा अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। यही नहीं, जब कभी ऐसी इजाजत दी भी गई तो राजनयिक कर्मियों की गहराई से निगरानी की जाती थी और जिससे अधिकारी नहीं चाहते ऐसे लोगों से बात करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके बावजूद चीनी अधिकारी लगातार यह दावा करते हैं कि तिब्बत विदेशी यात्रियों के लिए खुला रहता है। तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के चीनी तिब्बतविदों या अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने हाल के वर्षों में कई बार अमेरिकी कांग्रेस की यात्रा की है, लेकिन 1990 के दशक से ही अमेरिकी कांग्रेस का कोई भी सदस्य तिब्बत की यात्रा पर नहीं जा पाया है। कांग्रेस सदस्यों द्वारा हाल के वर्षों में तिब्बत की यात्रा के कई अनुरोधों को ठुकरा दिया गया है, जबकि कांग्रेसनल कर्मचारियों की कुछ यात्राओं की इजाजत 2008 के बाद दी गई है, लेकिन पूरी यात्रा साथ–साथ निगरानी करने वाले कर्मचारियों के साथ सख्त नियंत्रण में हुई है।

निर्वासित तिब्बती सांसदों ने यूरोपीय संसद के सात देशों का दौरा संपन्न किया

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 17 जून, 2014)

निर्वासित तिब्बती संसद के पांच सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने गत 15 जून को बर्न स्थित स्विस संसद के दौरे के साथ ही यूरोपीय संसद के सात देशों का दौरा संपन्न किया।

धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती संसद के पांच सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने गत 15 जून को बर्न स्थित स्विस संसद के दौरे के साथ ही यूरोपीय संसद के सात देशों का दौरा संपन्न किया। इन सांसदों ने स्विस संसद में तिब्बत के लिए गठित बहुदलीय समूह को भारत दौरे के लिए भी आमंत्रित किया। तिब्बतीय संसद के स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंल का स्वागत समूह की तरफ से श्रीमती टिएना मोजर (ग्रीन लिबरल पार्टी) और श्री मार्टिन नैफ (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी) द्वारा किया गया। निर्वासित तिब्बती संसद की वेबसाइट तिब्बत डॉट नेट पर 16 जून को यह जानकारी दी गई है।

निर्वासित तिब्बती सांसदों द्वारा दिए गए आमंत्रण पत्र में कहा गया है, "यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी, यदि आप और स्विस संसद में तिब्बत पर बहुदलीय समूह के आपके अन्य साथी निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा करें और भारत में निर्वासित तिब्बतियों की राजनीतिक स्थिति, तिब्बती संस्कृति और पहचान को बचाए रखने के बारे में एक आंतरिक दृष्टि हासिल करें।" इस प्रतिनिधिमंडल के साथ स्विस तिब्बतन फ्रेंडशिप के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री उलरिच सोल्टरमैन भी थे।

इस प्रतिनिधिमंडल ने स्विस सांसदों को यह भी बताया कि अगले साल स्ट्रासबर्ग/फ्रांस में तिब्बत पर सातवें विश्व सांसद सम्मेलन (डब्ल्यूपीसीटी) का आयोजन होने जा रहा है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इसमें स्विट्जरलैंड के सांसद भी शामिल होंगे।

स्विट्जरलैंड के दौरे के साथ ही इस प्रतिनिधिमंडल का सात देशों का यूरोप का दौरा संपन्न हुआ। यह दौरा 28 मई को बेल्जियम से शुरू हुआ था और इसमें एस्टोनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और आस्ट्रिया जैसे देशों का दौरा हुआ। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में श्री कर्मा छोफेल, श्री दावा फुंनकी, श्री जामयांग सोएपा और श्री वांगपो तेथोंग शामिल रहे।

चीन के विनाशकारी सोने की खदान का विरोध करने वाले 60 तिब्बतियों को हिरासत में लिया गया

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 15 जून, 2014)

तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के चामदो प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित जोगांग काउंटी के चीनी प्रशासन ने 8 एवं 9 जून को एक गांव से करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया है। रेडियो फ्री एशिया की 13 जून की खबर के अनुसार प्रशासन ने गेवार गांव के करीब हर परिवार के एक सदस्य को हिरासत में लिया है। इनमें पहले भारत की यात्रा कर चुके कुछ लोग और गांव के दो मुखिया भी शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन ने पहले तोंगबार कस्बे के गेवार गांव के सभी पुरुषों को एक बैठक के लिए बुलाया था। इसके अलावा गांव के दो मुखिया और पहले भारत की यात्रा कर चुके सभी लोगों को भी इस बैठक में बुलाया गया। बैठक में अधिकारियों ने आदेश दिया कि हर परिवार का एक सदस्य और गांव के मुखिया जोगांग काउंटी मुख्यालय जाएं जहां उनसे लगातार पूछताछ की जाती रही।

खनन का गांव वालों द्वार विरोध काफी समय से चल रहा है, लेकिन यह तब और जोर पकड़ गया, जब विरोध प्रदर्शन कर–कर के हताश हो चुके एक ग्रामीण फाकपा ग्यालत्सेन ने 7 मई को खुद को चाकू घोंप लिया और इसके बाद तोंगबार कस्बे की एक इमारत से छलांग लगाने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद तोंगबार सरकारी कार्यालय के बाहर सैकड़ों तिब्बती जमा हो गए और खदान को विकसित करने की चीनी योजना पर विराम लगाने की मांग की।

प्रशासन ने इन विरोध प्रदर्शन करने वालों का सख्ती से दमन किया और यह सुनिश्चित करने के कदम उठाए गए कि इस परिस्थिति के बारे में खबर गांव से बाहर न जा पाए। खबर में सूत्रों के हवाले से बताया कि तोंगबार कस्बे और आसपास के सभी गांवों में फोटो के आदान–प्रदान सहित अन्य सभी संचार माध्यमों पर सख्ती से निगरानी की जा रही है।

ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ने चीन में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई

(तिब्बत डॉट नेट, 17 जून, 2014)

चीन "बड़े पैमाने पर और सुनियोजित" मानवाधिकार उल्लंघन के लिए दोषी है। चीनी प्रधानमंत्री ली केक्यांग के तीन दिवसीय ब्रिटेन दौरे के पहले दिन ब्रिटिश उपप्रधानमंत्री निक क्लेग ने यह बात कही। ब्रिटेन के आम चुनावों के लिए पहले चरण के लिबरल डेमोक्रेट घोषणापत्र को जारी करते हुए उप प्रधानमंत्री ने यह बात कही।

उन्होंने कहा, "चीन के लोग एक पार्टी के शासन वाले कम्युनिस्ट शासन के लिए राजनीतिक रूप से बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हम आज भी चीन में जारी बड़े पैमाने के और सुनियोजित मानवाधिकार उल्लंघन और फांसी की सजा के व्यापक प्रचलन को नजरअंदाज नहीं कर सकते।"

ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्ते तब से खट्टे हो गए थे, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री ने वर्ष 2011 में दलाई लामा से मुलाकात की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को 2012 में चीन का अपना पूर्व निश्चित दौरा रद्द करना पड़ा था जब चीन ने कहा कि उसके नेताओं के पास कैमरन से मिलने के लिए समय नहीं है।

हालांकि, उप प्रधानमंत्री निक क्लेग ने जोर देकर कहा कि उन्हें इस मुलाकात का कोई पछतावा नहीं है और उन्हें फिर से परमपावन दलाई लामा से मुलाकात करने में बेहद खुशी होगी। उन्होंने कहा, "वास्तव में मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में भी उनके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिल सकूंगा, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि फिलहाल सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।"

उप प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ चीन आर्थिक आजादी के असाधारण रास्ते पर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ एक पार्टी वाली साम्यवादी व्यवस्था एक खुले, लोकतांत्रिक समाज की विरोधी है। उप प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब उसी दिन बाद में प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की चीनी प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी थी। चीनी प्रधानमंत्री की इस यात्रा से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तेजी आएगी।

अवैध चीनी खनन रोकने का विरोध कर रहे 27 तिब्बती गिरफ्तार

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 20 जून, 2014)

रेडियो फ्री एशिया की 18 जून की रिपोर्ट के अनुसार सोल्हो प्रशासनिक क्षेत्र के चाबछा काउंटी की चीनी पुलिस ने गत 6 से 7 जून को कुल 27 तिब्बतियों को गिरफ्ता कर लिया जो उस इलाके में सफेद संगमरमर के अवैध खनन का विरोध कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खदानों में अपने कॉन्ट्रैक्ट में तय लीज अवधि के पूरा हो जाने के बाद भी खनन कार्य हो रहा था और इन्होंने पवित्र बौद्ध स्थलों पर भी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। हिरासत में लिए गए सभी तिब्बती काउंटी के कारसेल गांव के रहने वाले थे और इन्होंने संकल्प लिया था कि अब इस इलाके में चीनियों द्वारा सफेद संगमरमर का उत्खनन बिल्कुल नहीं होने देंगे। हिरासत में लिए गए लोगों में गांव के दो नेता त्रोथार और बर्मा भी शामिल हैं। चार ग्रामीणों को बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन बाकी 23 अब भी हिरासत में हैं।

बताया जाता है कि इस इलाके में चीनियों द्वारा 1989 से ही खनन कार्य चल रहा है। हालांकि, खनन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने न केवल बेरोकटोक खनन कार्य जारी रखा, बल्कि उन स्थानों पर भी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया जो स्थानीय तिब्बती निवासियों के लिए पवित्र माने जाते हैं। यह अतिक्रमण दूसरे गांव की सीमा तक पहुंच गया।

चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे का तिब्बतियों ने किया विरोध

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 9 जून, 2014)

तिब्बती युवा कांग्रेस के नेतृत्व में नई दिल्ली में 8 जून को एक विरोध प्रदर्शन में करीब 100 तिब्बतियों ने हिस्सा लिया। चीनी प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में भारतीय राजधानी पहुंचे चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी का तिब्बती विरोध कर रहे थे। नई दिल्ली की तिब्बती कालोनी मजनू का टीला में हुए इस विरोध प्रदर्शन में तिब्बतियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि वह श्री वांग के साथ मीटिंग में तिब्बत का मसला उठाएं।

समाचार एजेंसी पीटीआइ की 8 जून की खबर में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) सिंधु पिल्लई ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने चीन विरोधी नारे लगाए और बाद में खुद ही चले गए। एएनआइ समाचार सेवा के मुताबिक इस दौरान चीनी झंडे भी जलाए गए। तिब्बती युवा कांग्रेस तिब्बतियों की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है जिसका उद्देश्य तिब्बत को चीनी कब्जे से आजाद करना है। दूसरी तरफ, धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती प्रशासन केवल चीनी शासन के तहत वास्तविक स्वायत्तता की ही मांग कर रहा है। चीन इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं समझता और दोनों को कथित "दलाई गुट" का हिस्सा बताता है। चीन तिब्बती युवा कांग्रेस को 'आतंकवादी संगठन' तो निर्वासित प्रशासन को 'अलगाववादी' बताता है। आइएएनएस समाचार सेवा की 8 जून की खबर के अनुसार धर्मशाला मुख्यालय वाले तिब्बती महिला संघ (टीडब्ल्यूए) ने भी श्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वह "चीन से यह कहें कि वह निर्वासित तिब्बती नेतृत्व से मिलने वाले वार्ता की पेशकश को स्वीकार करे।"

वांग इस साल चीनी राष्ट्रपति शी की यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर आए थे। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात की और 8 जून को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिले। इसके बाद 9 जून को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई। उनके विशेष प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में शामिल होने, जिसमें भारत–चीन सीमा विवाद पर चर्चा होनी थी और भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल से भी मिलने का कार्यक्रम था। भारत में नई सरकार के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्तों को सकारात्मक मोड़ देने के लिए वांग ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को "सामारिक मसलों पर मतभेदों की जगह ज्यादा आम सहमति बनानी चाहिए और वह चाहते थे कि दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करें कि सीमा मसले पर मतभेदों से "हमारे सामान्य रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

तिब्बती फिल्म निर्माता को चीनी जेल से रिहा किया गया

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 7 जून, 2014)

चीन ने गत 5 जून को एक शौकिया तिब्बती फिल्म निर्माता को रिहा कर दिया जिनकी छह साल की जेल की सजा पूरी हो गई थी। करीब 40 वर्ष के फिल्म निर्माता धोनढुप वांगछेन ने वर्ष 2008 में ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें आम तिब्बती लोगों से दलाई लामा, उस साल होने वाले बीजिंग ओलंपिक, चीनी शासन, तिब्बती जमीन पर बड़े पैमाने पर चीनियों को बसाने जैसे कई मसलों पर सवाल पूछे गए थे। धोनढुप वांगछेन को जेल से बाहर निकालकर क्विंघई प्रांत के बायान काउंटी में स्थित उनके गांव खोत्से में उनकी बहन के घर ले जाया गया जहां जेल से जाने में करीब दो घंटे लगते हैं। उनका परिवार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रहता है।

संभवतः हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा प्रचारित तिब्बती राजनीतिक कैदी धोनढुप वांगछेन ने अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 में समूचे तिब्बती पठार में आम तिब्बतियों का वीडियो इंटरव्यू करके चीन सरकार को नाराज कर दिया था। उन्होंने इस इंटरव्यू के वीडियो फुटेज को तिब्बत से बाहर भी भेजा था। उन्हें 23 मार्च, 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उनके इस फुटेज से 28 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसका शीर्षक है: "लीविंग फियर बिहाइंड" (भय को पीछे छोड़ा)। इसे अगस्त 2008 में होने वाले बीजिंग ओलंपिक के दौरान दिखाया गया। चीन ने कथित तौर पर "अलगाववाद को बढ़ावा देने" के लिए उन्हें जेल भेज दिया, जबकि उनके सहयोगी 44 वर्षीय भिक्षु गोलोग जिग्मे ग्यात्सो को कई बार हिरासत में लेकर बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और सितंबर 2012 में वह जेल से फरार हो गए। वह इसी साल 18 मई को धर्मशाला पहुंचे हैं। धोनढुप वांगछेन पर मुकदमा चलाया गया और शीनिंग माध्यमिक जन अदालत ने 28 दिसंबर, 2009 को उनको सजा सुनाई। उन्हें 6 अप्रैल 2010 को शिचुआन जेल में भेजा गया जहां उनके साथ काफी कठोर व्यवहार किया गया और उन्हें मार्च 2012 से कालकोठरी में डाल दिया गया था। उनकी रिहाई के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई याचिका और मानवाधिकार संगठनों सहित तमाम दूसरे लोगों की आलोचना की वजह से बाद में उन्हें शीनिंग शहर के क्विंघई महिला जेल में डाल दिया गया जहां स्थिति थोड़ी "सुधरी" हुई थी और उनके रिश्तेदार उनसे मिल सकते थे। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में रहने वाले अपने रिश्तेदार ग्यालजोंग सेट्रिन को उन्होंने फोन पर बताया था, "इस क्षण मैं अपने भीतर आंसुओं का समंदर देख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा स्वास्थ्य जल्दी सुधर जाएगा। जेल में मुझे जो कुछ सहयोग मिला मैं उन सबके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। मैं फिर अपने परिवार के बीच रहना चाहता हूं।" सेट्रिन ने ही तिब्बत से मिले फिल्म के आधार पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। यह साफ नहीं हो पाया है कि वास्तव में उन्हें कहां से रिहा किया गया। एक प्रेस बयान के अनुसार उन्हें क्विंघई प्रांत की राजधानी शीनिंग की एक जेल से रिहा किया गया। लेकिन ज्यादातर खबरों में बताया गया है कि उन्हें गांसू प्रांत के सांगछू काउंटी स्थित एक जेल से रिहा किया गया। सेट्रिन ने भी यही बताया है।

धोनढुप को उनके साहस के लिए लंदन स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सम्मानित किया है। कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, अमेरिका ने भी वर्ष 2012 में उन्हें इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया। पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही रिहाई के लिए याचिका अभियान चलाया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पिछले साल अमेरिका–चीन मानवाधिकार संवाद के दौरान भी इस मसले को उठाया था।

तिब्बत में नरसंहार के मुकदमे पर संसदीय अमान्यीकरण के आगे स्पेन की अदालत को झुकना पड़ा

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 27 जून, 2014)

पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन और पूर्व चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग

चीन के शीर्ष पांच रिटायर्ड नेताओं के खिलाफ अधिकृत तिब्बत में नरसंहार के मानवाधिकार उल्लंघन अपराधों के लिए गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के बाद स्पेन की राष्ट्रीय अदालत ने अब 23 जून को यह निर्णय लिया है कि वह इन नेताओं के खिलाफ लंबित दो मामलों को आगे नहीं बढ़ाएगी। इस साल फरवरी में स्पेन की संसद द्वारा कानून में बदलाव कर देने से अदालत को यह निर्णय लेना पड़ा है। संसद ने कानून में बदलाव करते हुए अदालत के सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र पर अंकुश लगा दिया था। चीनी नेताओं और वहां की सरकारी मीडिया द्वारा भारी आलोचना, धमकी तथा स्पेन की निंदा करने के बाद संसद ने कानून में बदलाव के विधेयक को तेजी से आगे बढ़ाया और इसे सिर्फ सत्तारूढ़ कं. जर्वेटिव पीपल्स पार्टी के सांसदों के समर्थन से पारित कर दिया गया।

पिछले 23 जून को एक बयान के द्वारा घोषित किया गया अदालत का यह निर्णय सर्वसम्मत से नहीं लिया गया। ज्यूरिस्ट डॉट ओआरजी की 25 जून की रिपोर्ट के अनुसार स्पेन की सर्वोच्च अदालत हाई कोर्ट के जजों ने 9–7 के वोट से चीनी मानवाधिकारों के उल्लंघन के दो खुले मामलों को खारिज कर दिया। जिन जजों ने इस मामले को बंद करने के खिलाफ वोट दिया था, उनका तर्क था कि कानून के राजनीतिक रूप से प्रेरित सुधार का संवैधानिक अदालत द्वारा परीक्षण होना चाहिए।

हाई कोर्ट के बहुसंख्यक आदेश में कहा गया कि मानवता के खिलाफ अपराध के मामले नए कानून के अनुरूप नहीं हैं जिसके द्वारा विदेश में हुए ऐसे अपराधों के जांच करने की स्पेन की क्षमता को सीमित कर दिया गया है। इस तरह के आदेश से कोर्ट ने उसी अदालत द्वारा अन्य सार्वभौमिक न्याय मामलों में जजों द्वारा पहले लिए गए निर्णयों से भी खुद को अलग कर लिया। कम से कम दो मामलों में जांच कर रहे जजों ने अपनी सुनवाई रोकने से इंकार करते हुए कहा था कि उनको यह न्यायिक क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय कानून से मिला है और इसे घरेलू कानून से सीमित नहीं किया जा सकता।

बीबीसी की 24 जून की खबर के अनुसार चीन ने तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में स्पेन की कोर्ट के इस नए आदेश का स्वागत किया है। हालांकि, कोर्ट का यह आदेश किसी भी तरह से अभियुक्त चीनी नेताओं के किसी तरह से निर्दोष साबित करने की वजह से नहीं है।

वास्तव में इस साल फरवरी में, कई साल की जांच एवं सुनवाई के बाद कोर्ट ने चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन, पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग, पूर्व राज्य सुरक्षा प्रमुख किआयो शी, पूर्व परिवार नियोजन मंत्री पेंग पियून और तिब्बत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व प्रमुख छेन कुइयान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। हाल में रिटायर हुए चीन के राष्ट्रपति और तिब्बत में पार्टी के पूर्व प्रमुख रहे हू जिनताओ के खिलाफ भी अक्टूबर 2013 में एक अभियोग आदेश जारी किया गया।

कानून में बदलाव के बाद अब स्पेन की अदालतें केवल तब ही किसी सार्वभौमिक न्याय याचिका पर सुनवाई कर सकती हैं, जब अभियुक्त स्पेन का नागरिक हो या स्पेन में रहने वाला कोई विदेशी हो, या कोई ऐसा विदेशी हो जिसके प्रत्यर्पण से स्पेन मना कर रहा हो। इसके अलावा, यह भी जरूरी है कि कथित पीड़ित अपराध होने के समय स्पेन का निवासी हो। इसके अलावा कानून में एक उपबंध को शामिल कर पहले इस मामले में चल रहे सभी जांच को रोक दिया गया, जिनमें चीनी नेताओं के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट भी शामिल था। मौजूदा मामले में याचिका स्पेन के ही तिब्बत अभियान संगठन *कमिटे डी अपोयो अल तिब्बत* द्वारा दायर किया गया था, इसमें एक पीड़ित तिब्बती भिक्षु भी शामिल थे, जो कथित चीनी अत्याचार के बाद स्पेन के नागरिक बन गए थे।

गत 13 जून को विपक्षी स्पैनिश सोशलिस्ट पार्टी के सांसदों ने स्पेन की मैड्रिड स्थित संवैधानिक अदालत में अपील कर यह मांग की है कि फरवरी 2014 में किए गए संशोधन को अमान्य कर दिया जाए। इस अपील में कहा गया था कि संशोधन से देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है और यह असंवैधानिक है। इसके अलावा इस संशोधन की देश की विपक्षी पार्टियों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, मीडिया और यहां तक कि न्यायपालिका के एक वर्ग द्वारा भारी आलोचना की गई है।

तिब्बती सिर्फ वास्तविक स्वायत्तता चाहते हैं, स्वाधीनता नहीं: सांगे

.(डॉयचे वेले, 7 जून, 2014)

तिब्बत के निर्वासित सरकार के नेता लोबसांग सांगे ने अपने नए अभियान के बारे में डॉयचे वेले (डीडब्ल्यू) से बात की जिसका उद्देश्य बीजिंग के साथ लंबे समय से बाधित वार्ता प्रक्रिया को फिर से शुरू करना और अपनी मातृभूमि पर चीन की पकड़ को नरम बनाना है।

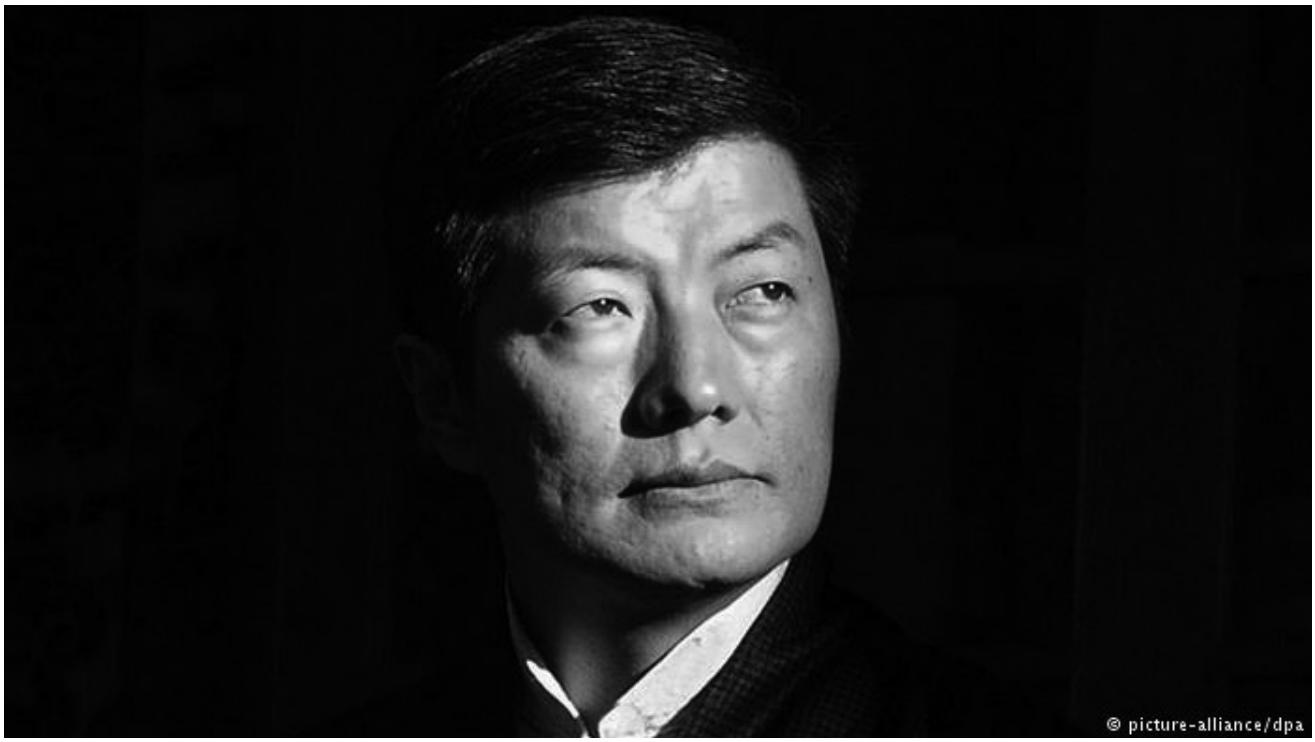

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के प्रधानमंत्री ने 'मध्यम मार्ग नीति' पर चलने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई जिसके तहत चीन सरकार से बातचीत के द्वारा वह तिब्बतियों के लिए चीन के भीतर ही एक 'वाजिब स्वायत्तता' हासिल करना चाहते हैं।

सांगे की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब सीटीए एक वैश्विक प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके द्वारा दुनिया भर की सरकारों को इस बात के लिए मनाने का प्रयास किया जाएगा कि वे चीन पर इस बात के लिए दबाव बनाएं कि वह निर्वासित तिब्बतियों के साथ फिर से वार्ता शुरू करे। चीन सरकार और सीटीए के बीच औपचारिक वार्ता वर्ष 2010 में बाधित हो गई थी, जब बीजिंग में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था और तिब्बत में काफी सख्त कार्रवाई शुरू की गई थी। चीन वर्ष 1950 से ही तिब्बत पर शासन कर रहा है और कई तिब्बतियों का यह मानना है कि बीजिंग के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व की वजह से उनके गहन बौद्ध संस्कृति के लुप्त हो जाने का खतरा है।

डॉयचे वेले से एक इंटरव्यू में सांगे ने यह उम्मीद जताई कि शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीन सरकार अपने सख्त रवैये की समीक्षा करेगी और तिब्बत के मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए वार्ता को ही एकमात्र रास्ता स्वीकार करेगी।

डीडब्ल्यू: यह देखते हुए कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मां एक बौद्ध थीं और उनके पिता के दलाई लामा से दोस्ताना रिश्ते थे, क्या आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों और खासकर तिब्बतियों के प्रति चीनी नेताओं के रवैए में कोई बदलाव देखा है?

सांगेः हमने यह खबरें सुनी हैं कि पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा चल रही है। हाल में कई विद्वानों ने अल्पसंख्यकों और तिब्बतियों के बारे में अपनी राय जाहिर की है। लेकिन हमने अभी तक चीनी नेताओं के रवैए में या तिब्बत में दमनकारी नीतियों की जमीनी स्थिति में कोई बदलाव होते नहीं देखा है।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चीन के बढते प्रभाव को निर्वासित तिब्बतियों द्वारा काफी अनुभव किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अब कम से कम सरकारें दलाई लामा से मिलने की इच्छुक रहती हैं। क्या समय चीन के पक्ष में चला गया है?

सांगेः चीन सरकार विभिन्न सरकारों पर दबाव डाल रही है कि वह दलाई लामा से न मिलें, साथ ही केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और उसकी मध्यम मार्ग नीति के बारे सरकारों को गलत जानकारी भी दी जा रही है।

हालांकि, जनता के स्तर पर तिब्बतियों में रुचि बनी हुई है और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम ज्यादा जागरूकता पैदा कर सकते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपने प्रति समर्थन मजबूत कर सकते हैं। समय चीन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 60 साल के कब्जे के बाद भी तीसरी पीढ़ी के तिब्बती चीन सरकार की कठोर नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि चीन के दावे के मुताबिक तो वे तिब्बतियों को दिए जाने वाली तमाम सुविधाओं के लाभार्थी हैं। असंतोष और विरोध प्रदर्शन जारी हैं। हाल के वर्षों में तिब्बत के भीतर और बाहर रहने वाले तिब्बतियों में एकता और एकजुटता की भावना जिस तरह से मजबूत हुई है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इस बुनियाद का तिब्बती संघर्ष को सहारा मिलेगा।

इस रविवार (8 जनू, 2014) को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। क्या भारत–चीन रिश्ते में सुधार से भारतीय शहर धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के दर्जे पर कोई जोखिम हो सकता है?

सांगेः जी नहीं। तिब्बत और तिब्बतियों के साथ व्यवहार पर भारतीय नीति एक ही बनी रही है, चाहे सत्ता में कोई भी रहे। हमारा मानना है कि हाल में चुनी गई नरेंद्र मोदी की सरकार भी ऐसी ही नीतियां जारी रखेगी। मुझे उम्मीद है कि चीनी विदेश मंत्री भारत की विविधता में एकता और लोकतंत्र की उस बुनियाद की सराहना किए बिना नहीं रह सकेंगे जो बहुभाषी, बहुजातीय भारत को एक देश के रूप में एकीकृत बनाए हुए है। हमारा मानना है कि यदि चीन सरकार भी तिब्बतियों के प्रति ऐसी ही नीतियां अपनाए तो इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा।

चीन सरकार से आप वास्तव में क्या उम्मीद करते हैं?

सांगेः हमें उम्मीद है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली सरकार अपने कठोर रवैए की समीक्षा करेगी और तिब्बतियों के प्रति उदार नीतियों की शुरुआत करेगी। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग यह स्वीकार करेंगे कि तिब्बत मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए संवाद ही एकमात्र रास्ता है।

आप किस हद तक बीजिंग के साथ समझौता करने को इच्छुक हैं?

सांगेः "मध्यम मार्ग नीति" में वास्तव में इन्हीं सब चीजों के बारे में है। हम तिब्बत में मौजूदा दमन को खत्म होते देखना चाहते हैं। यदि चीनी संविधान के ढांचे के भीतर ही हमें वाजिब स्वायत्तता मिल जाती है तो हम चीन से अलग नहीं होना चाहेंगे।

पिछले कुछ दशकों में चीनी शासन ने किस तरह से तिब्बत को प्रभावित किया है?

सांगेः पिछले कुछ दशकों में तिब्बत में लगातार राजनीतिक दमन, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक हाशियाकरण, पर्यावरण विनाश और सांस्कृतिक विलोपन जारी है, खासकर तिब्बत में चीनी जनसंख्या के बसने से ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से तिब्बती जनता में गहन असंतोष को हवा मिल रही है।

आपको इस बात की कितनी उम्मीद है कि चीन अपनी तिब्बत नीतियों की समीक्षा करेगा?

सांगेः देर–सबेर चीन को यह आभास होगा कि कठोर नीतियां काम नहीं कर रही हैं। तिब्बतियों द्वारा किए जाने वाले करीब 130 आत्मदाह से–जिसे हम हतोत्साहित करते हैं–चीन सरकार को यह साफ संदेश मिलना चाहिए कि अब समय आ गया जब परमपावन दलाई लामा के दूतों और चीन सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता शुरू करनी चाहिए।

क्या चीनी प्रशासन तिब्बत में भी उसी तरह की कठोर नीतियां अपना रहा है जैसा कि सीक्यांग में?

सांगेः जी हां। चीनी कब्जे से लेकर आज तक तिब्बतियों और उइगर के साथ चीनी प्रशासन का व्यवहार एक जैसा रहा है। साठ साल तक दमन करने से भी चीन को कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब समय आ गया है कि तिब्बती जनता की गरिमा के लिए, चीन के साथ सौहार्द बनाए रखने और शांति के लिए "मध्यम मार्ग नीति" को एक मौका दिया जाए।

सीमा की वजह से भारत–चीन में तकरार, फिर भी व्यापार में चाहते हैं गहरा रिश्ता

(न्यूयॉर्क टाइम्स, एलेन बैरी, 8 जून, नई दिल्ली, 2014)

चीन की सरकारी समाचार मीडिया ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत आर्थिक मामलों में एक व्यावहारिक नए साझेदार के रूप में किया है, यह बताते हुए कि एक प्रांतीय नेता के रूप में उन्होंने चार बार बीजिंग का दौरा किया था, निवेश आकर्षित करने के लिहाज से और उन्होंने उन्होंने अपना बिजनेस कार्ड चीनी अक्षरों में चमकते शुभ लाल रंग में छपवाया था।

लेकिन जब दो विशाल पड़ोसी इस हफ्ते शीर्ष स्तरीय बैठकों की पहली श्रृंखला के साथ अपने रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, एक तस्वीर इसमें अड़चन पैदा करने वाली लग रही है, एक तिब्बती व्यक्ति की जिन्हें मोदी के पिछले महीने हुए शपथ ग्रहण में सामने की सीट दी गई थी। वह व्यक्ति हैं लोबसांग सांगे, भारत स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री और ऐसे व्यक्ति जिन्हें चीन के नाराज होने के डर से आधिकारिक समारोहों में शायद ही कभी आमंत्रित किया जाता है। चीन ने कई बार निर्वासित और तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की निंदा करते हुए उन्हें अलगाववादी बताया है और कई बार दलाई लामा का स्वागत करने वाले विदेशी सरकारों से अपने राजनयिक रिश्तों पर कैंची चलाई है।

शपथग्रहण समारोह के दिन भी श्री सांगे हाल में नार्वे के प्रधानमंत्री से मिले अपमान से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहे थे, जिन्होंने दलाई लामा से मिलने से इंकार किया था और शुरू में वह समझ नहीं पा रहे थे कि नई दिल्ली से मिले आमंत्रण का क्या करें। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रमुख श्री सांगे ने कहा, "मैं सोचता था, कि हो सकता है कि मुझे पीछे बैठने का मौका मिले, जहां तक हो सके मुझे ओट में ही रखा जाएगा। लेकिन जब मैंने उन्हें अपना कार्ड दिखाया, तो उन्होंने मुझे सामने जाने को कहा।" केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की मांग है कि तिब्बत के तीनों परंपरागत प्रांतों को चीन के भीतर ही "वाजिब क्षेत्रीय स्वायत्तता" दी जाए। श्री सांगे इस समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अनुरोध पर पहुंचे थे–आरएसएस एक प्रभावशाली हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसने मोदी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद की है– लेकिन पिछले सप्ताह चीन द्वारा भारत के सामने औपचारिक शिकायत दर्ज करने से पहले इस पर लोगों ने खास ध्यान नहीं दिया था।

इस तरह दुनिया की दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में एक तरह का स्थायी तनाव बना रहा है, जो पिछले 50 साल से करीब 2,521 किमी. लंबी सीमा को साझा कर रहे हैं, तिब्बत क्षेत्र पर चीनी दावे के बाद। यहां तक कि जब श्री मोदी चीन के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते बनाना चाहते हैं, भारतीय सुरक्षा संगठनों से जुड़े लोगों को इसमें गहरा संदेह है।

श्री मोदी के आंतरिक सुरक्षा मामलों के जूनियर मंत्री (गृह राज्य मंत्री) उस अरुणाचल प्रदेश से आते हैं जिसके कुछ हिस्सों पर चीन अपना दावा करता है। रविवार को जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे तो एक भारतीय अखबार ने खबर छापी कि चीन पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। भारतीय खुफिया ब्यूरो के हवाले से लीक किए गए एक दस्तावेज का हवाला देते हुए यह खबर सामने आई थी। नई दिल्ली में रहने वाले सामरिक मामलों के प्रमुख विशेषज्ञ सी. राजामोहन ने कहा, "बुनियादी नजरिया यह है कि हमें कारोबारी पक्ष पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसका यह मतलब नहीं है कि सुरक्षा मसलों पर उनका नजरिया कुछ अलग होगा।" उन्होंने कहा कि, अपने पड़ोसी देशों जापान और वियतनाम के साथ कलहपूर्ण रिश्तों का सामना कर रहे चीन ने भी भारत को ऐसा ही संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वे यह संकेत दे रहे हैं कि वे अपने परिधि के इस हिस्से को मुनासिब और शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने सीमा विवादों के बारे में या पाकिस्तान के साथ उनके रिश्तों को कमतर करने कोई संकेत नहीं दिया है।"

मोदी के शपथग्रहण के बाद चीन का सार्वजनिक बयान पूरी तरह से सकारात्मक ही रहा है और श्री वांग ने दैनिक अखबार हिंदू से कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी के शपथ ग्रहण करने के बाद उन्हें 'व्यक्तिगत रूप से निर्देश देकर' जल्दी ही भारत दौरे पर जाने को कहा। वांग ने कहा कि वह मोदी के लिए यह संदेश लेकर आए हैं कि, "आप द्वारा सुधार एवं विकास के लिए और सपने को पूरा करने

के लिए किए जाने वाले सभी प्रयासों में चीन आपके पक्ष में खड़ा रहेगा।"

चीन ने भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के निर्माण और औद्योगिक विकास क्लस्टर्स को बढ़ावा देने में मदद करने की पेशकश की है और उसने संभावित स्थलों की जांच के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा है। श्री वांग ने कहा कि औद्योगिक केंद्रों में कई चीनी कारोबारी समूहों ने निर्माण कार्य भी शुरू किया है और उन्हें उम्मीद है कि इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्राथकिता वाली नीतियां अपनाई जाएंगी।

हालांकि, तनाव को देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रविवार की सुबह वांग जब अपनी पहली पूर्व निर्धारित बैठक में पहुंचते उससे पहले नई दिल्ली के सुरक्षा बलों को एक उत्तरी दिल्ली के एक तिब्बती बस्ती की घेराबंदी करनी पड़ी। तिब्बती युवा कांग्रेस से जुड़े सैकड़ों आंदोलनकारी चीनी दूतावास के बाहर एक भारी विरोध प्रदर्शन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। तिब्बती युवा कांग्रेस से जुड़े तेनजिंग जिग्मे ने कहा कि इन सभी लोगों को घेर लिया गया और बाहर नहीं निकलने दिया गया।

दो साल पहले राष्ट्रपति हू जिनताओ के भारत दौरे के समय एक 26 वर्षीय निर्वासित तिब्बती युवा ने चीन की दमनकारी नीतियों के विरोध में खुद को आग लगा ली थी जिसकी बाद में मौत हो गई थी। उसके इस कार्रवाई के फुटेज पूरी दुनिया के निर्वासित तिब्बती समुदाय में फैल गए और यह उन्हें उग्र करने वाली बात थी।

दिल्ली में निर्वासित तिब्बतियों के आंदोलन का सबसे मुखर समर्थक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है जिसने श्री सांगे को 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रित करने की सिफारिश की थी। संघ के एक पदाधिकारी राम माधव ने यह जानकारी दी।

धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार की संसद के स्पीकर पेम्बा सेरिंग ने कहा कि इस निमंत्रण से यह संदेश गया है कि सरकारों के बदलने के बाद भी "हम भारत में तिब्बत मसले को नीचे होता हुआ नहीं देखेंगे। विश्लेषक श्री राजा मोहन ने कहा कि निर्वासित तिब्बतियों के लिए समर्थन भारतीय समाज में गहराई तक विद्यमान है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। हम ही केवल बचे हैं जो उन्हें सहयोग दे रहे हैं। भारतीय ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो उन्हें आसरा दे रहे हैं और उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़े रहने को इच्छुक दिखते हैं।"

उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत सरकार 1960 के दशक के प्रबल वकालत वाले दौर में नहीं जा सकती, जब भारतीय सेना को सीमा पर घुसपैठ की वजह से चीन से एक छोटी सी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। मोहन ने कहा, "आगे ज्यादा समानुभूति और लगाव देखा जा सकेगा, लेकिन वे कितना कुछ करना चाहते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।"

पश्चिम को वश में करने का चीनी प्रयास

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शेष देश के साथ तिब्बत के एकीकरण को और गहरा बनाया

(21 जून, 2014, ल्हासा)

करीब आठ साल पहले जब खुला था तो गोलमुड से ल्हासा रेलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी रेल उद्यमों में से एक था। करीब 4 अरब डॉलर की लागत से 550 किमी. दूरी तक की पटरियां बिल्कुल बर्फ से जमे इलाकों में बिछाई गईं और 5,000 मीटर उन्नतांश पर पहुंचते हुए यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलमार्ग हो गया। इस साल सितंबर महीने तक इस रेल मार्ग का विस्तारित खंड ल्हासा से शिगास्ते भी खुल जाएगा, जो तिब्बत को शेष चीन से जोड़ने की भविष्य की योजना का पहला हिस्सा है। शिगास्ते का यह रेलमार्ग ल्हासा से 250 किमी. दक्षिण–पश्चिम की ओर जाता है और इसके लिए पांच घंटे की यात्रा करने की जगह अब रेल से दो घंटे में ही पहुंचा जा सकेगा। साथ ही साथ इससे पर्यटकों के लिए भी तिब्बत के दूसरे शहर तक पहुंचना आसान होगा। यही नहीं, इससे इस प्राकृतिक संसाधन बहुल क्षेत्र तक पहुंचना ज्यादा आसान हो जाएगा (चीनी लोग तिब्बत को शीजांग कहते हैं जिसका मतलब है "पश्चिमी खज़ाना")। शरद ऋतु में 400 किमी. लंबे एक और विस्तारित रेलमार्ग का निर्माण कार्य शुरू होगा, ल्हासा से निंगत्री तक। निंगत्री एक ऐसा काउंटी है जहां जलविद्युत उत्पादन की भारी संभावनाएं हैं।

वर्ष 2020 तक चीन सरकार का उद्देश्य तिब्बत को उसके पड़ोसी प्रांतों (सीक्यांग, सिचुआन, युन्नान) से जोड़ने के लिए कई और बड़े रेल मार्गों को पूरा करना है। इनमें से एक ल्हासा

से चेंगदू तक 1,900 किमी. लंबा रेलमार्ग है जिसकी लागत 20 अरब डॉलर से ज्यादा की है। शिगास्ते से न्यालम और ड्रोमो तक की नेपाल और भारतीय सीमा के करीब तक जाने वाले दो अन्य रेलमार्गों की चीनी योजना के भारत सरकार के कान खड़े हो गए हैं। पिछले हफ्ते ही भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 54 नई सीमा चौकियों को मजबूत करने का निर्णय लिया है। यह वही उत्तर–पूर्वी राज्य है जिस पर 1962 में चीन चढ़ाई कर चुका है।

कम्युनिस्ट पार्टी का बुनियादी ढांचा विकास का यह अभियान देश के गरीब पश्चिम को समृद्ध पूर्व से जोड़ने की उसकी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीक्यांग चीन का सुदूर उत्तर–पश्चिमी इलाका है जहां उइगर अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत से लोग चीन के शासन से खीजे हुए हैं और यातायात संपर्क बनाने को इस रूप में ही देखा जा रहा है कि चीन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च यह दिखाता है कि केंद्र सरकार आर्थिक विकास का इस्तेमाल अशांत पश्चिमी क्षेत्रों में शांति लाने के लिए करने के लिए दृढ़ है। सीक्यांग और तिब्बत में ऐसे बड़े पैमाने के प्रयासों की कीमत चुकानी पड़ रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आधुनिक तिब्बती अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर रॉबर्ट बार्नेट ने कहा, "इन नीतियों को आगे बढ़ा रहे लोग वास्तव में संस्कृति के संरक्षण और पर्यावरण जैसे 'छोटे' मसलों को नहीं देख पा रहे। यह चूहों के झुंड के ऊपर बुलडोजर के इस्तेमाल जैसा है।"

चीन के बाहर के बहुत कम लोग यह मानते हैं कि यह नीतियां कारगर हो रही हैं, खासकर वर्ष 2008 में समूचे तिब्बती पठार में फैली अशांति को देखते हुए। धार्मिक नियंत्रण के द्वारा तिब्बती भाषा का क्षरण, गहन निगरानी और सरकार की 'देशभक्तिपूर्ण शिक्षा' नीति परंपरागत धार्मिक विश्वास और रीति–रिवाजों को दमित करने के लिए लाई गई है। वर्ष 2009 से अब तक 130 से ज्यादा तिब्बतियों ने खुद को आग लगा लिया है। सामान्य तिब्बतियों के लिए तो तिब्बत से बाहर की यात्रा करना लगभग असंभव ही है और सीमा सुरक्षा को काफी सख्त कर दिया गया है। वर्ष 2008 से पहले तिब्बत से भागकर नेपाल आने वाले लोगों की संख्या सालाना 3,000 तक हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल यह संख्या घटकर सिर्फ 300 ही रह गई है।

इस बीच हान नस्ल के चीनी लोगों की तिब्बत में पर्यटक या कामगारों के रूप में आने की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले साल गोल्मुड से ल्हासा तक रेलवे से 75 लाख यात्रियों ने सफर किया जो तिब्बत की कुल जनसंख्या से भी दोगुना है। काफी दूरदराज के हिस्सा माने जाने वाले इलाकों तक पहुंच बढ़ने से यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी, जो अदूषित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध भूमि दिखाने के वायदे से आकर्षित होकर आते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह एक ऐसी भूमि है जिसमें काफी बदलाव आ रहा है।

ट्रेन जैसे–जैसे ल्हासा की ओर बढ़ती है, खिड़की से बाहर का दृश्य बदलता रहता है। घास भूमि के पार रिफाइनरियों की बड़ी–बड़ी चिमनियां और औद्योगीकरण के दूसरे संकेत दिखते हैं। तिब्बत का औद्योगिक विकास चीन के केंद्रीय और पूर्वी प्रांतों से काफी पिछड़ा हुआ है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के पास यह तकनीक और वित्तीय संसाधन मौजूद है कि तिब्बत जैसे कठिन इलाके में निर्माण कार्य कैसे किया जाए। सब कुछ यदि योजना के मुताबिक चलता रहा तो प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से आर्थिक तरक्की का सृजन होगा। पार्टी का अनुमान है कि तिब्बत में करीब 600 अरब युआन (96 अरब डॉलर) का खनिज संसाधनों का भंडार है। शिगास्ते के पास शेथोंगमन काउंटी में स्थित अकेले एक खदान से सालाना 5.3 करोड़ किलोग्राम तांबा, 1.90 लाख आउंस सोना और 24 लाख आउंस चांदी का उत्पादन होने का अनुमान है। इस क्षेत्र की जीडीपी का एक–तिहाई हिस्सा खनन से ही हो सकता है।

fjl&fjl dj feyxk ykHk \

इससे अर्थव्यवस्था का नाटकीय रूप से पुनर्गठन हो सकता है, जो कि कई दशकों से सरकारी सब्सिडी और सरकारी निवेश पर टिका हुआ है। पिछले साल इस इलाके की जीडीपी में 13 फीसदी की वृद्धि हुई है। चीनी कंपनियां और श्रमिक इसका फायदा उठा रहे हैंः तिब्बतियों में अक्सर भाषाई कौशल की कमी होती है और आगे बढ़ने के लिए उनके पास संपर्क नहीं रहता है। इसका नतीजा यह है कि राजस्व वापस पूर्व की ओर जा रहा है। हालांकि, रिस–रिस कर कुछ फायदा अब आम तिब्बतियों को मिलना शुरू हुआ है। अब गरीब से गरीब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की सालाना आय बढ़ रही है। सड़कों और रेलवे के विकास से उपभोक्ता वस्तुएं ज्यादा उपलब्ध हो रही हैं। कई सामाजिक योजनाओं का उद्देश्य भी लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। सरकार का कहना है कि पिछले साल पूरा हुए एक व्यापक जन विस्थापन परियोजना में 23 लाख लोगों का नए मकानों में बसाया गया है। समस्या यह है कि नए मकानों में बसाए गए ये लोग किसान हैं जो अपनी जमीन से कहीं और नहीं जाना चाहते थे। रेलवे की तरह ही तिब्बती पठार में छह एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें से चार वर्ष 2010 के बाद शुरू या विस्तारित हुए हैं और आगे दो नए एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है। दक्षिणी सीमा के नजदीक नए बनने वाले नए एयरपोर्ट्स ने पड़ोसी देशों को सचेत कर दिया है।

भारत सरकार के एक सुरक्षा सलाहकार ने उल्लेख किया कि क्षेत्रीय मसलों पर चीन ज्यादा "आक्रामक नीति" अपना रहा है। इस बीच प्रोत्साहन योजनाओं और सरकारी मंजूरी से ज्यादा से ज्यादा हान प्रवासी श्रमिक तिब्बत में आ रहे हैं। रेलवे नेटवर्क की वजह से यह प्रवाह और सुविधाजनक हुआ है। लांझू के रहने वाले 32 वर्षीय स्थूलकाय बिल्डर श्री झाओ तिब्बत में पहली बार वर्ष 2006 में आए थे। उन्होंने बताया कि हान चीनी होने के नाते पहले उनसे ल्हासा में अच्छी तरह से लोग पेश नहीं आए। श्री झाओ एक दिन पूरी तरह से लांझू लौट जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल तो तिब्बत में सड़कें और रेलमार्ग बनाने हैं।

तिब्बत: सीआइए'ज कैंसल्ड वार

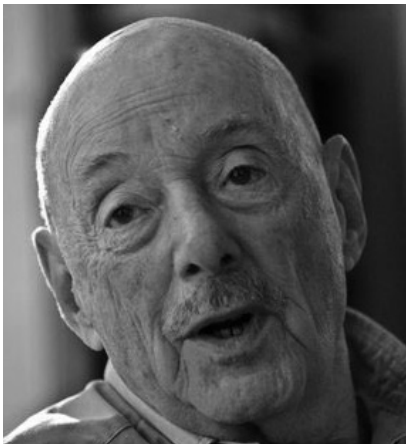

न्यूयॉर्क रीव्यू ऑफ बुक्स

जोनाथन मिरस्की
लेखक: जॉन केनेथ कनौस
पेज: 398
प्रकाशक: पब्लिक अफेयर्स (25 अप्रैल, 2000)
भाषा: अंग्रेजी

पिछली शताब्दी में काफी समय तक अमेरिका के तिब्बत से रिश्ते को चीन के सामने दंडवत झुकने और दलाई लामा के लिए खोखली शुभकामना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वर्ष 1908 में ही अमेरिकी राजनयिक विलियम रॉकहिल ने तेरहवें दलाई लामा को यह सलाह दी थी कि "चीन के साथ गहरे और दोस्ताना संबंध तिब्बत के लिए बिल्कुल जरूरी हैं और इसकी भलाई इसी में है कि ता सिंग (मांचू) साम्राज्य का हिस्सा बना रहे।"

एक सौ साल बाद चौदहवें दलाई लामा के साथ भी इस व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। वर्ष 2011 में राष्ट्रपति ओबामा के साथ व्हाइट हाउस के मैप रूम में एक मुलाकात के बाद–ओवल ऑफिस में मुलाकात ज्यादा आधिकारिक हो जाती–दलाई लामा को कूड़े के कनस्तरों को पार करते हुए पिछले दरवाजे से बाहर ले जाया गया। यह सब निश्चित रूप से इसलिए था कि चीन की निंदा से बचा जाए जो कि तिब्बत नीति की अपनी मामूली आलोचना को भी 'आंतरिक मामलों में दखल' मानता है।

हालांकि, इस मामूली आलोचना के रवैए से अमेरिका ने अब काफी दूरी बना ली है। वर्ष 1950 में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद करीब दो दशकों तक सीआइए ने एक गुप्त अभियान चलाया जिसका उद्देश्य तिब्बती चरमपंथियों को प्रशिक्षित करना और चीन के बारे में खुफिया सूचनाएं जुटाना था। यह दुनिया भर में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के अमेरिकी प्रयासों का ही हिस्सा था। आज भी इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को कम जानकारी है, लेकिन इससे कम से कम एक बार जबर्दस्त खुफिया आघात किया गया था और इसके द्वारा दलाई लामा को सहयोग का स्रोत भी प्रदान किया गया। रिचर्ड निक्सन के वर्ष 1972 में माओ से ऐतिहासिक मुलाकात को तय तिथि के एक दिन पहले ही अचानक निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अमेरिका अपने तिब्बत के बारे में अपनी परंपरागत नीति पर लौट आया। हालांकि, इससे चीनी–अमेरिकी संबंधों में अविश्वास की लंबी विरासत का अंत नहीं हुआ। चीन सरकार न सिर्फ सीआइए के कार्यक्रम के बारे में जानती थी, बल्कि उसने 1992 में इस विषय पर एक श्वेतपत्र भी प्रकाशित किया था। इस श्वेतपत्र में सीआइए की गतिविधियों के बारे में भरोसेमंद पश्चिमी सूत्रों से हासिल जानकारी को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें चरमपंथ के लिए मुख्यतः "दलाई लामा गुट" को जिम्मेदार ठहराया गया, एक ऐसी भाषा जिसका चीन आज भी इस्तेमाल करता है।

चीन की जनमुक्ति सेना द्वारा तिब्बत पर चढ़ाई के बाद जब तिब्बती राष्ट्रवादियों की हार हुई और जब चीन ने दलाई लामा को इस इलाके पर चीनी प्रशासन का प्रभुत्व स्वीकार करने को मजबूर किया तो 1955 में स्थानीय तिब्बतियों के एक संगठन ने गुप्त रूप से एक सशस्त्र जनक्रांति की योजना बनाई और एक साल बाद ही विद्रोह हो गया। बागियों ने स्थानीय सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया और सैकड़ों कर्मचारियों और हान चीनी लोगों की हत्या कर दी। मई 1957 में एक विद्रोही संगठन और एक विद्रोही लड़ाकू दस्ते का गठन किया गया और कम्युनिस्ट अधिकारियों की हत्या शुरू हो गई, संचार लाइनों को बाधित कर दिया गया और तिब्बत क्षेत्र में स्थित चीनी सरकारी संस्थाओं और चीनी सैनिकों पर हमले किए गए।

तब तक बागियों को अमेरिकी सहयोग हासिल हो गया था। 1950 के दशक के शुरुआती वर्षों में सीआइए ने कम्युनिस्ट चीन पर अंकुश के लिए अपने बढ़ते अभियान के हिस्से के तहत तिब्बतियों का सहयोग करने का रास्ता निकालना शुरू कर दिया था।

दशक के दूसरे अर्द्धांश में "प्रोजेक्ट सर्कस" की औपचारिक शुरुआत की गई, तिब्बती प्रतिरोधी लड़ाकों को प्रशिक्षण के लिए हवाई जहाज से अमेरिका ले जाया गया और तिब्बत के महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर प्लेन से ही हथियार और गोला–बारूद गिराए गए। वर्ष 1959 में सीआइए ने कोलोराडो के लीडेविले पास कैम्प हेल में तिब्बती लड़ाकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक गुप्त केंद्र की शुरुआत की। इस स्थान का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि यह समुद्र तल से 10,000 फुट ऊंचाई पर है जो हिमालयी क्षेत्र के लगभग बराबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोलराडो प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 170 "कम्बा गुरिल्ला" तैयार हुए।

सीआइए ने खुद कभी चीनी कब्जेदारों के खिलाफ एक जनक्रांति का नेतृत्व नहीं किया, लेकिन इसे शीतयुद्ध के सबसे महान खुफिया सफलताओं में से एक हासिल हुई, जब तिब्बती लड़ाकों ने चीनी सेना के दस्तावेजों का एक बड़ा खजाना हासिल किया और इसे 1961 में सीआइए को सौंप दिया। इससे चीनी सैनिकों का मनोबल गिर गया जिन्हें यह पता चल गया कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के समय चीन में भारी अकाल आया हुआ था। अगले कुछ दशकों में हालांकि, तिब्बत में सीआइए की गतिविधियों को लेकर वाशिंगटन में ही असहमति बढ़ने लगी और 1971 में हेनरी किसिंगजर ने जब निक्सन की माओ से

मुलाकात तय कराई, तब तक यह कार्यक्रम ठंडा पड़ चुका था।

सीआइए में 40 साल काम कर चुके जॉन केनेथ कनौस अपनी 1999 में आई पुस्तक *ऑर्फन्स ऑफ द कोल्ड वारः अमेरिका ऐंड द तिब्बतन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल* में याद करते हैं, "बीजिंग से वार्ता की मेज पर तो तिब्बत कभी मसला नहीं रहा है, लेकिन तिब्बत आंदोलन को अमेरिका का आधिकारिक समर्थन का युग भी खत्म हो चुका है। किसिंजर के नए समीकरण में तिब्बत के लिए कोई भूमिका नहीं थी।" वर्ष 1975 तक राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड चीन के भविष्य के नेता शक्की देंग जियोपिंग से यह कहने में सक्षम हो सके, "मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं उप–प्रधानमंत्री जी कि जहां तक तिब्बत की बात है, हम अमेरिकी सरकार के किसी भी कार्रवाई का विरोध करते हैं, समर्थन नहीं।"

तिब्बत के बहुत से दोस्त और दलाई लामा के, जो कि हमेशा अहिंसा की वकालत करते रहे हैं, के प्रशंसक यह मानते हैं कि उन्हें सीआइए कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। लेकिन दलाई लामा के एक भाई ग्यालो थोनढुप इस अभियान से गहराई से जुड़े थे और इस अभियान में शामिल रहे कनौस लिखते हैं कि, "ग्यालो थोनढुप ने अपने भाई दलाई लामा को सीआइए के सहयोग के लिए सामान्य शर्तों की जानकारी दे दी थी।"

वर्ष 1999 में मैंने दलाई लामा से पूछा था कि क्या सीआइए का ऑपरेशन तिब्बत के लिए नुकसानदेह रहा है, तो उन्होंने कहा था, "जी हां, यह सच है।" उन्होंने कहा कि यह दखल हानिकारक रहा है क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य अमेरिकी हितों की रक्षा करना था, बजाय किसी भी तरह से तिब्बतियों की मदद करने के। उन्होंने मुझसे कहा था, "एक बार चीन के प्रति अमेरिकी नीति में बदलाव आया, उन्होंने मदद बंद कर दी। नहीं तो हमारा संघर्ष आगे बढ़ता। बहुत से तिब्बतियों को सीआइए के सैन्य साजो–सामान हवाई जहाज से गिराने से बहुत उम्मीद थी, लेकिन चीनी सेना ने उसे अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर दिया। तिब्बतियों के लिए अमेरिकियों का अलग एजेंडा था।"

यह बिल्कुल सही बात थी, और सीआइए तथा तिब्बतियों के अलग लक्ष्यों का पूरी तरह खुलासा तिब्बती बोलने वाली मानव विज्ञानी करोले मैकग्रानहन ने वर्ष 2010 में आई अपनी पुस्तक *अरेस्टेड हिस्ट्रीजः तिब्बत, द सीआइए ऐंड मेमरीज ऑफ अ फॉरगटेन वार* में किया है। हालांकि, उनके इस किताब में आपको कई बार मानव विज्ञान के जटिल शब्दावली का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह बहुत ही उम्दा तरीके से यह बताता है कि तिब्बती बुजुर्ग लड़ाके सीआइए के अभियान के अनुभव को कैसे आखिर अमेरिकियों से अलग बताते हैं।

एक जबर्दस्त उदाहरण चीनी सेना के दस्तावेजों का मामला है जिसे एक उच्च स्तर के चीनी अधिकारी के ऊपर घात लगाकर किए गए तिब्बती हमले के बाद हासिल किया गया था। इसका वाशिंगटन स्थित सीआइए के म्यूजियम में लगे एक विशाल पेंटिंग में भयानक विवरण के साथ इसका वर्णन किया गया है। चीनियों के नैतिक बल कमजोर होने के खुलासे के साथ ही इस दस्तावेज में यह खुलासा किया गया कि तिब्बत में चीनियों द्वारा किस हद तक हिंसा की जा रही है। मैकग्रानहन कहती हैं, "यह सूचना चीनी अत्याचारों का एकमात्र दस्तावेजी सबूत थे और इसलिए यह अनमोल थे।" हालांकि, पुराने लोगों के लिए लंबे इंटरव्यू में इस दस्तावेज के बारे में जानकारी बहुत कम है।

सवाल उठता है कि, "आखिर इस विशेष उपलब्धि को अमेरिका और तिब्बत की सरकार ने जितना महत्व दिया, उतना यह सैनिकों के लिए यादगार क्यों नहीं?"

इसकी वजह यह है कि तिब्बती लड़ाकों को इस दस्तावेज की कीमत के बारे कुछ नहीं बताया गया था, जिसे वह खुद नहीं पढ़ सकते थे। एक बुजुर्ग लड़ाके उन्हें बताते हैंः "हमारे सैनिकों ने चीनी ट्रकों पर हमले किए और चीन सरकार के कुछ दस्तावेज बरामद किए। इसके बाद अमेरिकियों ने हमारे तनख्वाह बढ़ा दिए। कोई नहीं जानता था कि उन दस्तावेजों में क्या है। उस समय किसी ने सवाल नहीं पूछे। यदि आप ज्यादा सवाल पूछते तो दूसरे लोग आप पर संदेह करते।"

इस घात वाले हमले के अगुआ ने उन्हें बताया, "पुरस्कार के रूप में सीआइए ने मुझे एक ओमेगा का क्रोनोग्राफ दिया।" हालांकि उन्हें भी इन दस्तावेजों के महत्व के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मैकग्रानहन ने काफी गहन विवरण के साथ यह दिखाया है कि बुजुर्ग इन सबसे ऊपर दलाई लामा के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते थे और चाहते थे कि वह स्वाधीन तिब्बत के नेता के रूप में अपनी स्थिति को फिर से हासिल करें।

सीआइए का अभियान खत्म होने के बाद तिब्बत लगातार वाशिंगटन की चीन नीति में हाशिए पर जाता गया। कनौस ने अपनी दूसरी पुस्तक *बियांड शांग्री–लाः अमेरिका ऐंड तिब्बत्स मूव इन्टू द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी* में इसे साफ किया है। सच्चाई यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब चीन के रूप में एक वैश्विक ताकत का सामना कर रहे हैं। तिब्बत को नजरअंदाज करने वाली नीति को जायज ठहराने वाली भाषा बोलते हुए पूर्वी एशिया के पूर्व सहायक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल ग्रीन कनौस को बताते हैं, "तिब्बतियों की मदद के लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे, सिवाय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अपने रिश्ते सुधारने के ताकि हम उन पर इस बात के लिए दबाव बना सकें कि वे तिब्बतियों के प्रति नरम नीति अपनाएं।" ग्रीन यह स्वीकार करते हैं कि, "यह शायद इसे तर्कसंगत बनाना था।"

राष्ट्रपति ओबामा जल्दी ही चीन के नए नेता शी जिनपिंग से मिलेंगे। उनके सलाहकार उन्हें उस संवाद की याद जरूर दिलाएंगे जो 27 जून, 1998 को उनके पूर्ववर्ती बिल क्लिंटन और तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन के बीच हुआ था। उस मुलाकात में क्लिंटन ने जियांग को यह आश्वासन दिया था, "मैं इस बात से सहमत हूं कि तिब्बत, चीन का एक हिस्सा है, चीन का एक स्वायत्तशासी इलाका। मैं समझ सकता हूं कि आखिर क्यों इसे दलाई लामा से बातचीत के लिए पूर्व शर्त होना चाहिए।" अपने प्रख्यात आकर्षण का सहारा लेते हुए क्लिंटन ने यह भी कहा था, "मैंने दलाई लामा के साथ समय बिताया है। मैं उन्हें एक ईमानदार आदमी मानता हूं और मेरा मानना है कि यदि राष्ट्रपति जियांग के साथ उनकी बातचीत हुई होती तो आप दोनों एक–दूसरे को बहुत पसंद करते।" बताया जाता है कि इसके बाद जियांग जोर से हंसे थे। क्लिंटन के इस सुझाव को मुलाकात के आधिकारिक चीनी विवरण से बाहर कर दिया गया।